जिसकी वजह से शरीफ आदमियों को भी वकील भाड़े पर मिल सकें ?

SHRI MURLIDHAR CHANDRA-KANT BHANDARE: I really object to that, Sir. He is not understanding the professional integrity of the lawyer at all, when he functions in a court.

SHRI N. K. OP. SALVE: in regard to discharging the functions nobody knows better than what I do. *(Interr. upiAons)...*

Modernisation of Textile Mills

*324. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the proposals under Government's consideration for modernisation of textile mills;

(b) what is the number of textile mills that are presently rated as uneconomic; and

(c) what assistance will be given to make these units viable?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में आई डी बी आईने 1986 में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना (टी एम एफ एस) शुरू की थी जिसका उद्देश्य उपस्कर/मशीनों के प्रतिस्थापन/नवीकरण के जरिए वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण के उन्नयन, उत्पाद-क्वालिटी में सुधार लाने तथा निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के ऋण अर्थात् आधुनिकीकरण ऋण तथा विशेष ऋण मिलों को दिए जाते हैं । वस्त्र मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है कि इस योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिये सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना की धनराशि को बढ़ाकर के 1500 करोड़ रुपये कर दिया जाए । आई डी बी आई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 31 जुलाई, 1991 तक इस योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए 501 आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

बी आई एफ आर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार फिलहाल 199 वस्त्र मिलें खर्चीली/रुग्ण पाई गई हैं।

SHRI KAMAL MORARKA: The hon. Minister in his reply has said that his Ministry has asked for an increase in the corpus of the Textile Modernisation Fund Scheme to Rs-1,500 crores and 501 applications are pending with the IDBI. Does the Min ister know the total amount required in the 501 applications and whether this increase to Rs. 1,500 crores is enough? I am asking this question because in the current Government's policy export has got a very import ant role to play. The Minister knows that textile is the single largest area where exports can be stepped up. Not only the export problem, but the employment problem also can be solved if an integrated policy in this regard is made. So, my question is whether this Rs. 1500 crores for this would be enough; if not, whether his Ministry is going to take it up for a larger increase in the outlay.

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन साहब, 501 अप्लीकेशंस की जो बात की गयी है उसके अन्तर्गत 357 अप्लीकेशंस को सेंक्शन किया गया है, करीब 1366.39 करोड़ इसका अमाउंट है । 500 अप्लीकेशंस का जो टोटल अमाउंट है वह करीब 22 सौ करोड़ रुपया है और जो अमाउंट डिसबर्स हुआ है वह करीब 812 करोड़ रुपया का अमाउंट डिस्बर्स हुआ है । इसको देखते हुए 15 सौ करोड़ रुपया हमने प्रपोज किया है । लेकिन यह भी अभी स्वीकृत नहीं हुआ है । हमारी कोशिश है कि हम 15 सौ करोड़ रुपये कम से कम लें क्योंकि आई०डी०बी०आई०

अपने रैगुलर बजट में से भी इस प्रकार की स्कीमें चलाता है । इसलिये उनका कहना है कि क्योंकि हम रैगुलर स्कीम चला रहे हैं इसलिये इसके अन्तर्गत ही हम इसको लेंगे ।

SHRI KAMAL MORARKA: The Abid Husain Committee Report is with the Government. Because mod ernisation forms a very important part of the recommendations of the Abid Husain Committee Report, I would like to know whether the Government is likely to implement the report and what is the Government's reaction to the Report.

श्री अशोक गहलोत : चेयरमन साहब, आबिद हुसैन कमटी ने भी 15 सौ करोड़ रुपये रेकमेंडेशन की थी । हम इस बात को मानते हैं कि मार्डनाइज्ड इसका सबसे बड़ा पार्ट है । टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मार्डनाइज्ड करने से ही सारी प्राबलम हल हो सकती है। इसलिये अधिक से अधिक इस फंड के अन्तर्गत पैसा आई डी बी०आई० रख सके और अधिक से अधिक मार्डनाइज्ड हो, यह हम चाहते हैं।

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल : जो 199 मिलें बी०आई०एफ०आर० में अन-एकानामिकल और अन-वाइबल हैं, तो उनका आप क्या करेंगे ? आप उन 199 मिल्स का क्या करेंगे जिनको बी०आई०एफ०आर० में अन-एकानामिकल और अन-वाइबल बताया है ?

श्री सभापति : जवाब दीजिये।

श्री अशोक गहलोत : बी आई एफ आर० की जो स्कीम्स हैं, उनके अन्तर्गत सेमी-जूडीशियल बाडी है, 46 मिलों का तो उसने रीहैबलीटेशन प्लांट बना लिया है और 28 मिलों को उसने बंद करने का फैसला किया है । बाकी 125 केसेज उनके यहां पेंडिंग हैं । उनकी पूरी जांच कर रहे हैं ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, while implementing the modernisation scheme, will the Minister go to the market for selling the shares? May I also know from the Minister whether they are prepared to sell the unused land of the NTC for raising more funds?

श्री अशोक गहलोत : सभापति जी, एन०टी०सी० ने . . (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN; Question Hour Is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Delay in Execution of Projects .in Orissa

*325. SHRI JAGADISH JAIN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several multipurpose projects in Orissa like the Indravati, Upper Kolab and Subarnarekha Projects have been delayed;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) the steps taken to expedite the implementation of those projects?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRl H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. Multi-purpose Projects like Indravati, Upper Kolab and Subarnarekha have been delayed due mainly to proliferation of such Projects in the States, huge spill over of ongoing projects, floods and problems relating to land acquisition and construction.

(c) The expeditious implementation of these Projects depends primarily on the State Governments. However, Planning Commission has been stressing the need for prioritisation in. funding such projects for their expeditious implementation.